

शक्करयुक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स की तैयारी

मोटापे से निपटना आज कई देशों में जन स्वास्थ्य की एक प्राथमिकता बन चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटापा कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है और उनका बोझ जन स्वास्थ्य तंत्र को ही उठाना होता है। इससे निपटने के एक उपाय

के रूप में यूके एकेडमी ऑफ मेडिकल रॉयल कॉलेज ने सिफारिश की है कि शक्करयुक्त पेय पदार्थों (सॉफ्ट ड्रिंक्स) पर उसी तरह टैक्स लगाया जाना चाहिए, जैसे सिगरेट पर लगाया जाता है।

इस तरह के टैक्स के पीछे विचार यह है कि टैक्स लगाने पर इन पेय पदार्थों की खपत में गिरावट आना लाज़मी है और यदि लोग इनका सेवन कम करेंगे तो मोटापे में भी ज़रूर कमी आएगी। उदाहरण के लिए हंगरी में 2011 में फूड टैक्स लागू किया गया था और वहां देखा



गया था कि मात्र 6 माह में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री 117 लाख लीटर से घटकर मात्र 69 लाख लीटर रह गई थी।

यूके एकोडमी ऑफ रॉयल मेडिकल कॉलेज ने इस बाबत एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के साइमन केपवेल ने बताया है कि

कैलोरी खपत को कम करने से संभावित स्वास्थ्य लाभ की बात क्यूबा की अर्थ व्यवस्था में मंदी के दौरान साफ हुई थी। *अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडिमियोलॉजी* में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक जब आर्थिक मंदी आई तो आम नागरिकों की खपत में प्रतिदिन 1000 कैलोरी की कमी आई थी। एक दशक में मोटापे का प्रकोप आधे से भी कम रह गया था और मधुमेह तथा दिल के दौरों में क्रमशः 51 और 35 प्रतिशत की कमी देखी गई थी। **(स्रोत फीचर्स)**